Dainik Jagran
17.12.2020

चीनी निर्यात के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : किसानों के गन्ना बकाया भुगतान और चीनी के भारी स्टॉक से हलकान चीनी मिलों को राहत देने के लिए सरकार ने बुधवार को 3,500 करोड़ की निर्यात सब्सिडी मंजूर की है। सब्सिडी की यह राशि सीधे गन्ना किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। सब्सिडी चालू चीनी वर्ष (2020-21) के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर दी जाएगी। इससे गन्ना किसानों के एरियर भुगतान में मदद मिलेगी।

दरअसल, चीनी उद्योग जहां एक तरफ भारी चीनी स्टॉक से परेशान है, वहीं भुगतान न होने से गन्ना किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार के इस फैसले से दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। देश में कुल पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों के साथ इसका लाभ उन पांच लाख कामगारों को भी मिलेगा, जो चीनी मिलों और उससे संबद्ध कार्यों से जुड़े हैं। चालू चीनी वर्ष में कुल उत्पादन 3.10 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि चीनी की कुल घरेलू खपत 2.60 करोड़ टन रहने वाली है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जताई है।

पेराई सीजन का ढाई महीना बीत चुका है। थाइलैंड में चीनी का उत्पादन घटने की वजह से इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में भारतीय चीनी निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं। सरकार के इस फैसले से पूरी उम्मीद है कि चालू चीनी वर्ष में 60 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इससे चीनी उद्योग को निर्यात सब्सिडी समेत कुल 18,000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इससे गन्ना भुगतान करने में मिलों को बड़ी राहत मिलेगी। चीनी उद्योग के लिए यह बड़ी खबर है कि पिछले सीजन की निर्यात सब्सिडी के भुगतान के लिए सरकार ने 5,300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। इससे भी गन्ना किसानों को भुगतान हो सकेगा। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए विशेष खुशी का दिन है। करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान पिछली निर्यात सब्सिडी के लिए